

प्रिय,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्श,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
उत्तरांचल, नैनीताल ।

न्याय अनुभाग :

देहरादून : दिनांक : ६ सितम्बर, 2006

विषय: 12वें वित्त आयोग, भारत सरकार द्वारा संस्तुत अनुदानों के अन्तर्गत, मा० उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल परिसर में स्थित बैरक संख्या 3ए से 6ए(चार भवन) के विशेष मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1013/यू.एच.सी./एडमिन.बो/निर्माण/2005, दिनांक 19.4.06 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 12वें वित्त आयोग, भारत सरकार द्वारा संस्तुत अनुदानों के अन्तर्गत, मा० उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल परिसर में स्थित बैरक संख्या 3ए से 6ए(चार भवन) के विशेष मरम्मत हेतु रु० 33,24,000/- के आगणन के विरुद्ध टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत रु० 32,74,000/- (रुपये बत्तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन (प्रति संलग्न) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त संस्तुत आगणन के विपरीत रु० 32,74,000/- (रुपये बत्तीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से त्नी गई हों, की स्वीकृति निम्नानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
- (2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जाय, तदुपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।
- (3) कार्य को स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में लागत के पुनरीक्षण के लिए शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी ।
- (4) एक मुरत प्राविधान की कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर निम्नानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय ।
- (5) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।
- (6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर ली जाय । निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणों के अनुरूप कार्य किया जाय ।
- (7) आगणन में धनराशि जिन मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।
- (8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय ।

- (9) जी०पी०डब्ल्यू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।
- (10) किसी भी कार्यालय/संस्थाओं के निर्माण को विस्तृत आगणन गठित करते समय स्वीकृत ज्ञातव्य एवं नार्मस के अनुसार गठित किया जाव तथा उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय ।
- (11) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज बुक्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (12) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XVI/219(2006), 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपनोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या 07 के अन्तर्गत लेखा-शीर्षक "2059-लोकनिर्माण कार्य-80-सामान्य-053-रख रखाव तथा मरम्मत-01-केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुणेनिर्गतित योजनाएँ-0101-12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भवनों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-591/XXVII(5)/2006, दिनांक 26.9.06 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीया,

(इन्दिरा आशोष)

सचिव ।

संख्या-12-दो(1)/XXXVI(1)/2006-तदुद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इकाई), ओवरग्रेड बिल्डिंग, उत्तरांचल, भाजरा, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
4. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल ।
5. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तरांचल शासन ।
6. एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।